

भाग-III**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 फरवरी, 2024

संख्या का०आ० 8/पं०अ० IV/1872/धा० 39क/2024.— हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 के नियम 12 के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 61/पं० अ० IV / 1872 / धा० 39क / 2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 61/पं०अ० IV / 1872 / धा० 39क / 2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 में, क्रम संख्या 1, 2 तथा 4 और उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी तथा प्रथम नवम्बर, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	विवरण	राशि
"1.	मानदेय	₹ 11000/- (केवल ग्यारह हजार रुपये) प्रति मास
2.	वर्दी भत्ता	₹ 4000/- (केवल चार हजार रुपये) प्रति वर्ष
4.	साइकिल भत्ता	₹ 3500/- (केवल तीन हजार पाँच सौ रुपये) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार"

अनिल मलिक,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 8th February, 2024

No. S.O. 8/P.A. IV/1872/S. 39A/2024.— In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) and (2) of rule 12 of the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O. 61/P.A. IV/1872/S. 39A/2018, dated the 13th September, 2018, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O. 61/P.A. IV/1872/S. 39A/2018, dated the 13th September, 2018, for serial numbers 1, 2 and 4 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st November, 2023, namely:-

Serial No.	Particulars	Amount
“1.	Honorarium	Rs. 11,000/- (Eleven thousand rupees only) per month
2.	Uniform Allowance	Rs. 4,000/- (Four thousand rupees only) per year
4.	Bi-cycle Allowance	Rs. 3,500/- (Three thousand five hundred rupees only) once in every five years”.

ANIL MALIK,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.